

प्रेषक,

डॉ० बी०वी०आर०सी० पुरुषोत्तम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 16 नवम्बर, 2021

विषय:- प्रदेश में वर्ग-3 भूमि के पट्टेदारों/कब्जाधारकों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने तथा वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जाधारकों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-958/दिनांक 02 नवम्बर, 2020 तथा शासनादेश संख्या-959/02 नवम्बर, 2020 की समयावधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासन द्वारा शासनादेश संख्या-958/XVIII(II)/2021-07(46)/2008, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जों एवं पट्टेदारों को भूमिधरी का अधिकार प्रदान करते हुए विनियमितीकरण किये जाने तथा शासनादेश संख्या-959/XVIII(II)/2021-07(46)/2008, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रदेश में वर्ग-3 की भूमि के पट्टेदारों को संक्रमणीय भूमिधरी का अधिकार प्रदान करते हुए विनियमितीकरण किये जाने के आदेश निर्गत किए गये हैं। सम्प्रति उक्त शासनादेशों के प्रभावी रहने की समय-सीमा 02 नवम्बर, 2021 को समाप्त हो चुकी है।

2- उक्त शासनादेशों की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सन्दर्भों पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-958/XVIII(II)/2021-07(46)/2008, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 तथा शासनादेश संख्या-959/XVIII(II)/2021-07(46)/2008, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 की समय-सीमा इस शासनादेश निर्गत होने की तिथि से आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

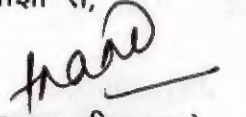
(डॉ० बी०वी०आर०सी० पुरुषोत्तम)
सचिव।

संख्या-1553/XVIII(II)/2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
 - 2- प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 - 3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 - 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
 - 5- आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
 - 6- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
- ✓ गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(डॉ० आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।